973/963

दैनिक जागरण

पृ० - 11

29 - 07 - 2015

कृषि विज्ञान केंद्रों को सरकार की 'दो टूक'

सात केवीके संचालक संस्थाओं पर गिर सकती है सरकार की गाज

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

- कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के लिए तैयार हो रही तबादला व प्रमोशन नीति
- दलहन व तिलहन पैदावार बढ़ाने की मिलेगी जिम्मेदारी

दूसरी हरितक्रांति को सफल बनाने में कृषि विज्ञान केंद्रों की अहम भूमिका के मद्देनजर उन्हें मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। लेकिन, इस अभियान में नाकाम साबित होने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों को बदलने में सरकार कोताही नहीं बरतेगी। खराब प्रदर्शन करने वाले ऐसे केवीके का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं को सरकार ने दो टूक चेतावनी दे दी है। केवीके में नियुक्त कृषि वैज्ञानिकों की दशा सुधारने की दिशा में सरकार पहल करेगी, चाहे वे किसी के अधीन हों।

देशभर में कुल 642 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में से सर्वाधिक 435 का संचालन राज्य सरकारों के अधीन चलने वाले कृषि विश्वविद्यालय करते हैं। जबकि, 93 केंद्रों का प्रबंधन गैर सरकारी संगठनों के हाथ में होता है। खराब प्रदर्शन करने वाले सात ऐसे केंद्र हैं जिनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। बाकी 55 केवीके केंद्र सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास होता है। इनमें सभी प्रबंध संस्थानों की अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग होता है। यहां काम करने वाले कृषि वैज्ञानिकों का न तो प्रोमोशन होता है और न ही तबादला। इन के हाल बंधुआ मजदूरों जैसा हो चुका है। इन केवीके के लिए धन का आवंटन केंद्र सरकार करती है और प्रबंधन दूसरे के हाथ में होता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार केवीके वैज्ञानिकों के गिरे मनोबल को उठाने की पहल करेगी। उनकी दशा सुधारने की दिशा में तैयारियां की जा रही हैं। फ्रंट लाइन प्रदर्शन करने वाले कृषि वैज्ञानिकों के गिरे मनोबल को उठाने के लिए सरकार उनकी हर जरूरत को पूरा करेगी। खराब प्रदर्शन करने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों की हर साल समीक्षा की जाएगी, जिसमें लगातार विफल होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से दलहन व तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। तिलहन पैदावार बढ़ाने का दायित्व 300 केवीके और दलहन के लिए 200 केवीके को सौंपा गया है।

कृषि विज्ञान केंद्रों के पटना सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर अमल करने की भी रणनीति तैयार की गई है। शहद उत्पादन बढ़ाने, खेती में ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने, सभी गांवों के खेतों की मिट्टी जांच व उपज के प्रसंस्करण जैसे मसलों को प्राथमिकता के तौर पर पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन केवीके के कमजोर कंधों पर डाले जाने की संभावना है।

सुनीता गुप्ता 29/7/15

प्रभारी पत्रिका एवं समाचार पत्र अनुभाग

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, निदेशक कार्यालय
2. निजी सचिव, संयुक्त निदेशक (प्रसार)
3. निजी सचिव, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)
4. निजी सचिव, अधिष्ठाता/संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
5. प्रभारी, पी. पी. आई
6. प्रभारी, कैटैट
7. प्रभारी, यू. एस. आई.